राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2011–12

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
506, मिनी सचिवालय, बनीपार्क
जयपुर – 302016

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना / उद्देश्य	1–2
2	निर्देशन एवं प्रशासन	2–6
3	राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र	7–10
4	विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण	10–13
5	विज्ञान एवं समाज	13–16
6	विज्ञान उद्यान	16–17
7	उद्यमित्ता विकास	17–18
8	अनुसंधान एवं विकास	18–19
9	जैव प्रौद्योगिकी	19
10	पेटेन्ट सूचना केन्द्र	20

प्रस्तावना

राजस्थान प्रदेश के चहूंमुखी विकास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्याओं के हल के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में की गयी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रूचि पैदा हो, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों तथा समाज में गरीब लोंगों के आर्थिक उत्थान में इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से आदान प्रदान करना है।

राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीक को उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रोत्साहित करना एवं राज्य की नितियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकों के उपयोग हेतु सलाह एवं सहयोग प्रदान करना। विभाग के विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियो का क्रियान्वयन विभाग में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों यथा अजमेर (मुख्यालय जयपुर), बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के माध्यम से किया जा रहा है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त विभाग के अधीन स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, राजस्थान सरकार, जौधपुर भी कार्यरत है।

उद्देश्य

- सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य सरकार को नीति निर्धारण हेतु सहयोग प्रदान करना।
- सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों विशेषकर पिछड़ेपन, बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या के समाधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना।
- विश्वविद्यालयों शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना एवं छात्र/छात्राओं को विज्ञान के प्रति रूझान उत्पन्न करना। उत्कष्ठ केन्द्रों की स्थापना एवं उनका संचालन।
- राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के लाभप्रद उपयोग हेतु संस्थानों/संगठनों के सहयोग से विभाग एवं अनुसंधान परियोजनाओं के निर्धारण की शुरूआत/सहयोग/सहायता/समन्वय स्थापित करना।
- अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नये वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे– नैनो टैक्नोलॉजी, बायोटैक्नोलॉजी, उपग्रह संचार, प्लाजमा, तकनीकियों/ प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों के लिये ई–बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर, इत्यादि की शुरूआत करना।
- राज्य के लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने एवं विज्ञान को लोकप्रिय करने हेतु विज्ञान पार्क/विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कर वैज्ञानिक ज्ञान का विसरण करना।
- विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय की शिक्षा की शुरूआत अवस्थिति का आंकलन एवं विज्ञान विषय के अध्ययन हेतु सुदृढ़ीकरण करने हेतु कार्य योजना का निर्धारण।
- प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं सफल प्रौद्योगिकियों को राज्य के विभागों के माध्यम से पुनरावृत्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों/सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं से सहभागिता करना।

- राज्य की वैज्ञानिक संस्थाओं एवं अन्य राज्यों की विज्ञान परिषदों से कार्यक्रम आधारित सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
- सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के माध्यम से राज्य के प्राकृतिक संस्थानों का डॉटाबैस तैयार करना एवं इन आंकड़ों का उपयोग विज्ञान परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु किया जाना।
- मानव संसाधन विकास की विशिष्ट आवश्यकता पहचान हेतु उद्योगों एवं एकेडेमिया में संबंध स्थापित करने की संभावनायें खोजना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व्यक्तियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता आधारित प्रशिक्षण आयोजित करना।
- राजस्थान राज्य के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण का निर्धारण।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गैप्स के चिन्हीकरण में सहायता एवं व्यूहरचना बनाने में सेतू का काम करना।
- आधारभूत स्तर के नवप्रर्वतकों की सृजनशीलता को उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों को मान्यता प्रदान करने एवं उनके नवाचारों को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रों एवं अनुसंधान एवं विकास के कार्यो हेतु इनाम एवं पारितोषिक की स्थापना।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार की ऐसी व्यवस्था किया जाना जिसमें सभी प्रकार के आविष्कारकों को बौद्धिक सम्पदा के सृजन एवं संरक्षण हेतु प्रेरणा मिल सकें एवं इस पद्धति के अन्तर्गत लोकहित में इन आविष्कारों के लिये एवं प्रभावी देशीय वाणिज्यकरण हेतु प्रभावशाली, सहयोग एवं विशुद्ध नीति परिवेश का निर्माण करना।

निर्देशन एवं प्रशासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का निदेशालय मिनी सचिवालय, जयपुर में स्थित है। विभाग द्वारा संचालित राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, जोधपुर में स्थित है जहां विशिष्ठ प्रशिक्षित वैज्ञानिक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर (मुख्यालय जयपुर) एवं जोधपुर में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय तथा कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर में स्थित विज्ञान केन्द्र विभागीय कार्यकमों को गति प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं विज्ञान लोकप्रियकरण की अनेक गतिविधियां, ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्रो व विज्ञान ग्रामों के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विभाग में दिनांक 31.12.2011 को कुल 132 पद स्वीकृत है। जिसमें से 105 पद आयोजना भिन्न मद में तथा 27 पद केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत हैं। बजट मद वार पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

बजट मदवार पदों की स्थिति

मद	स्वीकृत पद
आयोजना भिन्न	105
केन्द्र प्रवर्तित योजना	
अ. स्टेट कौंसिल	23
ब. केप परियोजना	4
योग	132

कार्यालयवार स्वीकृत पदों का विवरण :–
मुख्यालय, जयपुर

क.सं.	पद	बजट मद		
		आयोजना भिन्न	स्टेट कौंसिल	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	निदेशक	0	1	1
2	उपनिदेशक (आयोजना)	0	1	1
3	परियोजना निदेशक	1	2	3
4	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
5	परियोजना अधिकारी	0	4	4
6	अनुसंधान अधिकारी	3	3	6
7	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	0	1	1
8	लेखाकार	1	0	1
9	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	0	1
10	कनिष्ठ लेखाकार	2	0	2
11	सहायक क्यूरेटर	1	0	1
12	कनिष्ठ अभियंता	1	0	1
13	कार्यालय सहायक	0	1	1
14	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	0	2	2
15	सांख्यिकी सहायक	2	0	2
16	निजी सहायक	1	3	4
17	पुस्तकालयाध्यक्ष	0	1	1
18	शीघ्रलिपिक	1	1	2
19	वरिष्ठ लिपिक	2	0	2
20	तकनीशियन	1	0	1
21	कनिष्ठ लिपिक	5	0	5
22	वाहन चालक	3	0	3
23	साईकिल सवार	1	0	1
24	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	0	6
योग		33	20	53

राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, जोधपुर

क्र.सं.	पद	बजट मद			
		आयोजना भिन्न	स्टेट कौंसिल	केप प्रोजेक्ट	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	परियोजना निदेशक	1	0	0	1
2	परियोजना अधिकारी	1	0	0	1
3	अनुसंधान अधिकारी	6	0	4	10
4	सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	1	0	0	1
5	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी	2	0	0	2
6	शीघ्रलिपिक	0	1	0	1
7	वरिष्ठ प्रारूपकार	2	0	0	2
8	कनिष्ठ प्रारूपकार	10	1	0	11
9	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	0	0	1
10	सूचना सहायक (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	0	1	0	1
11	वरिष्ठ लिपिक	1	0	0	1
12	सर्वेयर	1	0	0	1
13	रेकार्ड कीपर	1	0	0	1
14	कनिष्ठ लिपिक	5	0	0	5
15	वाहन चालक	1	0	0	1
16	अनुरेखक	5	0	0	5
17	फैरोमेन	2	0	0	2
18	सिक्योरिटी गार्ड	1	0	0	1
19	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	0	0	4
20	निजी सहायक	1	0	0	1
21	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	0	1
22	कार्यालय सहायक	1	0	0	1
	योग	48	3	4	55

क्षेत्रीय कार्यालयवार स्वीकृत पदों का विवरण

क.सं.	पद	बजट मद		
		आयोजना भिन्न	स्टेट कौंसिल	योग
1	2	3	4	5
क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा				
1	परियोजना अधिकारी	1	0	1
2	अनुसंधान अधिकारी	1	0	1
3	सहायक क्यूरेटर	1	0	1
4	टेक्नीशियन	1	0	1
5	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	0	2
क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर				
1	अनुसंधान अधिकारी	2	0	2
2	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	1
4	वाहन चालक	1	0	1
क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर				
1	अनुसंधान अधिकारी	2	0	2
2	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	1
4	वाहन चालक	1	0	1
क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर				
1	परियोजना अधिकारी	1	0	1
2	अनुसंधान अधिकारी	1	0	1
3	कनिष्ठ लिपिक	1	0	1
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	0	1
क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, मुख्यालय, जयपुर				
1	परियोजना अधिकारी	1	0	1
2	अनुसंधान अधिकारी	1	0	1
3	वाहन चालक	1	0	1
योग		24	0	24

विभाग की वार्षिक योजना वर्ष 2011–12 में विभिन्न मदों में प्रावधित एवं व्यय (31.12.2011 तक) राशि निम्न हैं:–

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12					
		वित्तीय (रू. लाखों में)			भौतिक (संख्या में)		
		कुल आवंटन	व्यय दिसम्बर, 2011 तक	संम्भावित व्यय मार्च, 2012 तक	कुल लक्ष्य	दिसम्बर, 2011 तक कुल उपलब्धि	मार्च, 2012 तक कुल सांम्भावित उपलब्धि
A.	आयोजना						
1	अनुसंधान एवं विकास	955.00	9.53	955.00	270	21	270
2	विज्ञान एवं समाज	163.85	12.10	163.85	66	1	66
3	विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण	707.96	132.00	703.42	5178	1036	5178
4	जैव प्रौद्योगिकी	31.73	0.35	5.00	18	0	18
5	स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर	137.08	17.70	53.13	0	0	0
6	उद्यमिता विकास	8.24	3.20	8.19	75	65	75
7	पेटेंट सूचना केन्द्र	3.45	0.00	0.01	0	0	0
8	सूचना पद्धति प्रबंधन (MIS)	7.04	1.40	7.04	0	0	0
9	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निर्माण कार्य	47.95	12.93	20.00	0	0	0
	योग	***2062.30***	***189.21***	***1915.64***	***5607***	***1123***	***5607***
B.	केन्द्र प्रवर्तित योजना						
1	स्टेट कौंसिल	119.81	63.31	80.79	0	0	0
2	केप परियोजना	28.30	12.73	20.11	0	0	0
	योग	**148.11**	**76.04**	**100.90**	**0**	**0**	**0**
C.	आयोजना भिन्न	401.61	290.00	404.00	0	0	0
	योग	**401.61**	**290.00**	**404.00**	0	0	0
महायोग (A+ B+C)		**2612.02**	**555.25**	**2420.54**	**0**	**0**	**0**

आलोच्य वर्ष में विभाग द्वारा सम्पादित मुख्य कार्यक्रम :–

(अ) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुच्छेद 153 अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प आय वर्ग के परिवारों के लगभग 7 हजार मेधावी छात्र–छात्राओं को सेटकॉम के माध्यम से इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग की शुरूआत 01 जून, 2011 से की गई। अब तक कुल 211 कोचिंग व्याख्यानों का प्रसारण सेटकॉम स्टूडियों के SIT/ROT टर्मिनल पर किया गया।

(ब) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुच्छेद 154 की अनुपालना में राज्य में प्रथम बार 27–31 दिसम्बर, 2011 तक 19वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर में किया गया।

(स) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुच्छेद 155 की अनुपालना में नैनो टैक्नोलॉजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान विश्वविद्यालय में सेन्टर ऑफ कन्वर्जिंग टैक्नोलॉजी के तहत नैनो टैक्नोलॉजी सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है।

(द) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुच्छेद 156 "राजीव गांधी विज्ञान क्लब येाजना" अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लोकप्रियकरण एवं संचार हेतु राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 3171 विज्ञान क्लबों की स्थापना हेतु राशि रू. 3,17,10,000 की स्वीकृतियां जारी की गई।

(य) भारतीय अतंरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से राज्य में 51 स्वचालित मौसम केन्द्रों (AWS) की स्थापना की जा चुकी है एवं 249 स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

(र) राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहलय परिषद (NCSM) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से जयपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं जोधपुर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

(ल) झालरापाटन (झालावाड़) में विज्ञान पार्क की स्थापना की जाकर जन समुदाय के अवलोकनार्थ समर्पित।

(व) राज्य जैव प्रौद्योगिकी नीति (B.T.Policy) का प्रारूप तैयार किया गया।

गतिविधियां एवं कार्यक्रमः–

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित परियोजनायें/इकाईयों का संचालन एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं:–

1. .राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र
2. विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण
3. विज्ञान एवं समाज
4. विज्ञान उद्यान
5. उद्यमिता विकास
6. अनुसंधान एवं विकास
7. जैव प्रौद्योगिकी
8. पेटेन्ट सूचना केन्द्र

राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र

सुदूर संवेदन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी से परिपूर्ण यह केन्द्र राज्य में विकास योजनाओं के निर्माण में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का Spatial & Temporal Data के आधार पर GIS Based Data base तैयार करने में कार्यरत है।

केन्द्र का मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागो तथा गैर सरकारी संस्थानो के लिए राज्य की विकास परियोजनाओ में सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से भागीदारी निभाना है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नांकित खण्डों मे विभाजित किया गया:–

अ. अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओ में भागीदारी निभाना।
ब. भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित परियोजनाओ में भागीदारी।
स. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओ के निर्माण एवं कार्यो के निष्पादन में भागीदारी निभाना।
द. राज्य में सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के प्राध्यापको एवं छात्र–छात्राओं (अभियान्त्रिकी कॉलेज) को इस तकनीक की जानकारी एवं उपयोगिता इत्यादि हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
य. राज्य मे प्रशिक्षित व प्रचार गतिविधियों हेतु उपग्रह आधारित तन्त्र की स्थापना करना।

वर्ष 2011–12 में संचालित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है :–

(1) **फसल के क्षेत्रों एवं उत्पादन का पूर्वानुमान ज्ञात करना :–** स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार, अहमदाबाद द्वारा शत प्रतिशत आर्थिक सहयोग से उपरोक्त परियोजना वर्ष 1987–88 से निरन्तर प्रगति पर है। परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 22 जिलों मे गेहूँ, 16 जिलों मे सरसों एवं 2 जिलों मे कपास 3 जिलों में धनिया एवं 3 जिलों मे जीरा फसल के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रों एवं उत्पादन का पूर्वानुमान भू–उपग्रह चित्रों के डिजिटल व्याख्याकरण द्वारा किया जा रहा है इसके अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तर पर क्षेत्रफल एवं उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण राज्य के लिए भी गेहूँ एवं सरसों के लिए भी किया जा रहा है। मार्च, 2012 तक परियोजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सम्पूर्ण कार्य पूर्ण किया जायेगा। इससे राज्य के कृषि, राजस्व मण्डल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग लाभान्वित होगें।

(2) **जी॰आई॰एस॰ आधारित वन संसाधन विकास योजनाओं को तैयार करना:–** राज्य के वन विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य में वन संसाधन के लिए जी.आई.एस. आधारित डेटा बेस तैयार करने का कार्य केन्द्र में प्रगति पर है। अब तक राज्य के निम्न जिलों के जयपुर–96, करौली–06, बॉरा–97, धौलपुर–19, चूरू– 05, भरतपुर–11, कोटा, भीलवाडा– 233, सीकर– 56, दौसा– 39, अलवर–75, एवं टोंक–13 मैप्स ;1 : 4000 पैमाने पर व फोरेस्ट ब्लॉक्स के नक्शों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कोटा, भीलवाडा एवं अन्य का कार्य प्रगति पर है। इससे राज्य का वन विभाग लाभान्वित होगा ।

(3) **राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन सूचना पद्धति :–** उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत तैयार राज्य के सभी जिलों के भू उपयोग एवं भू वर्गीकरण मानचित्रों को अपडेट करने का कार्य प्रगति पर हैं वर्ष के निर्धारित 6 जिलों में 4 जिलों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अन्य जिलों भीलवाड़ा, चितौडगढ़, राजसमन्द एवं उदयपुर का कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार से तैयार डेटा बेस राज्य के सभी विभागों की प्राकृतिक संसाधन विकास योजनाओं के निर्माण में तथा गैर सरकारी संस्थानो के लिए भी उपयोगी है।

(4) **उपग्रह आधारित सूचना तन्त्र की स्थापना :–** राज्य मे उपग्रह आधारित सूचना तन्त्र के अन्तर्गत जयपुर में अपलिंक स्टेशन की स्थापना की जा चुकी है तथा राज्य के सभी जिला परिषद मुख्यालयों एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर क्रमशः SIT एवं ROT स्थापित किये जा चुके हैं। उपरोक्त के अन्तर्गत स्टूडियो भी कार्यरत हैं तथा अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण प्रगति पर है। कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का निरन्तर प्रसारण हो रहा है एवं इसके अतिरिक्त सेटकॉम स्टूडियो, जयपुर से 211 कोचिंग व्याख्यानो का प्रसारण माह दिसम्बर, 2011 तक हो चुका है।

(5) **जिलेवार भौगोलिक सूचना पद्धति मृदा उर्वरा एवं सूचना पोषक तत्व कमी के जी. आई. एस. नक्शे तैयार करने हेतु :–** जिला वाईज मृदा उर्वरा के जी. आई. एस. नक्शे कृषि विभाग के द्वारा तैयार करवाये जा रहे हैं। 33 जिलों के 340 नक्शे तैयार कर कृषि विभाग को उपलब्ध करवाये जायेंगें। उनका उपयोग विभिन्न फसलो में पोषक तत्व की आवश्यकता की जाँच कर किसान समय पर उर्वरकों का प्रयोग कर सकेगें, जिससें राज्य में बोई जाने वाली फसलों का उत्पादन बढेगा।

(6) **भू सरंक्षण एवं जल–ग्रहण के उच्च रिजुलेशन उपग्रह चित्रों से जल–ग्रहण के नक्शे तैयार करना :–** राज्य के 110 जलग्रहण के भूमि उपयोग, रोड, रेल, नहर, नदी नाले ढलान, कन्टूर के नक्शे तैयार कर मृदा संरक्षण एवं जलग्रहण विभाग को उपलब्ध कराने है जिनमें से 40 जलग्रहण का कार्य दिसम्बर 2011 तक पूर्ण किया जा चुका है। शेष जलग्रहण का कार्य प्रगति पर है और 31 मार्च, 2012 तक विभागीय लक्ष्य पूर्ण कर लिए जाऐंगें। इस परियोजना सें मृदा एवं जल संरक्षण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग लाभान्वित होगें।

(7) **भू–आकृति एवं लिनियामेनट के नक्शे तैयार करना :–** यह परियोजना नेशनल रिमोट सेन्सिंग सेन्टर, हैदराबाद, स्पेस विभाग द्वारा दी गई जिसमें बॉसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले का कार्य प्रगति पर है। जिसका उपयोग भूमि के जल स्रोतो एवं खनिजो के स्थान को पहचान करने मे मदद होगी।

(8) **ग्राम स्तर के प्राकृतिक संसाधनों के नक्शे तैयार करना (1:10,000 पैमाना):–** यह परियोजना नेशनल रिमोट सेन्सिंग सेन्टर, हैदराबाद, स्पेस विभाग द्वारा दी गई जिसके अन्तर्गत मृदा, भूमि उपयोग, धलान, रोड, रेल, नदी एवं नाले आदि के नक्शे तैयार किये जायेंगें। इस परियोजना हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों की योजना बनाने में किया जा सकेगा।

(9) **सिंचित क्षेत्रों में फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन :–** बीस सिचिंत क्षेत्रों में गेहूँ एवं सरसों की फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन सेटेलाईट चित्रों की मदद से किया गया।

(10) **स्वचालित मौसम केन्द्रो की स्थापना :–** भरतीय अन्तरिक्ष विभाग (इसरो) के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागो में 300 स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, जिन पर लगभग 5 करोड. 50 लाख रूपये की लागत आयेगी। जिनमे से 51 स्थानो पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (AWS) स्थापित किये जा चुके है एवं अन्य 250 की सूची इसरो को उपलब्ध करा दिया गया है। इसरो इनके लिए स्थापना की कार्यवाही कर रहा है। इनका उपयोग फसल बीमा फसल उत्पादन पूर्वानुमान, पैदावर बढाने हेतु उचित उपायों हेतु किया जा सकेगा।

(11) **राज्य में सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं इन्जीनियरिंग छात्र/छात्राओं को सुदूर संवेदन तकनीकी जानकारी :–** वर्ष भर में तीन अल्पकालीन प्रशिक्षण सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग हेतु आयोजित किये जाते है। जनवरी, 2012 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मृदा संरक्षण एवं जल–ग्रहण विभाग की आयोजित की जा चुकी है। अन्य दो प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी, 2012 में आयोजित किये जायेंगें। इसके अतिरिक्त करीबन 225 इन्जीनियरिंग के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है।

विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण

राज्य में वैज्ञानिक वातावरण निर्माण, जन–साधारण में वैज्ञानिक रूचि विकसित करने एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए दैनिक जीवन को सरल एवं सुलभ रूप से व्यतीत करने हेतु उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सम्पादित किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है:–

(1) **विज्ञान केन्द्र द्वारा सम्पादित गतिविधियां**

वर्ष 2011–12 में विज्ञान केन्द्र, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर में दूरबीन निर्माण कार्यशाला, कम्प्यूटर जागृति कार्यशाला, विज्ञान नाटक एवं चित्रकला प्रतियोगिता सम्पादित की गयी। इसके अतिरिक्त इन केन्द्रों पर आडियो विजुअल हॉल एवं कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर में स्थापित विज्ञान केन्द्र के सभागार को सुसज्जित किया गया।

(2) **विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रमों का आयोजन**

विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूचि, स्वयं अपने हाथों से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिये राज्य की तकनीकी संस्थानों/कार्यालयों तथा इन क्षेत्रों में नवीनतम विकास की जानकारी हेतु टेक्निकल टूर का आयोजन किया गया। वर्ष 2011–12 में राशि रू. 7.90 लाख के कार्यक्रम विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे है।

(3) **विज्ञान लोकप्रियकरण प्रतियोगितायें**

राज्य के विद्यार्थियों में पाठ्यत्तर प्रवृत्तियों की ओर आकृर्षित कर उनके बौद्धिक एवं सृजनात्मक विकास एवं उनमें प्रतियोगिता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा

विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित विभिन्न विद्यार्थी प्रतियोगिताओं का विवरण निम्नानुसार है।

(3.1) राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज प्रतियोगिता

वर्ष 1991 से विभाग द्वारा राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन कर उनमें आगे बढाने की आकांक्षा एवं जिज्ञासा जागृत करने हेतु इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह प्रतियोगिता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के सहयोग से सम्पन्न करायी गयी, जिनमें कक्षा 9 में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को राज्य के सभी जिलों में चयनित 48 केन्द्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा में राज्य के प्रथम 20 विद्यार्थियों को गौरव पदक एवं योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया गया। प्रथम विद्यार्थी को राशि रू. 4000/– नकद एवं शेष 19 को राशि रूपये 2000/– नकद प्रदान की गयी तथा 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया।

(3.2) राज्य स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता

राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के घोषित परिणामों में राज्य के चयनित प्रतिभावान विद्यार्थियों में से प्रत्येक जिले के प्रथम दो विद्यार्थियों के मध्य विज्ञान क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन पहले खण्ड स्तर, फिर राज्य स्तर पर किया जाता है। विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खण्ड स्तर पर क्विज प्रतियोगिता के आयोजन पश्चात् विजेता टीम राज्य स्तर की क्विज प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। इस प्रतियोगिता के खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले दल को रू. 1000/– का तथा द्वितीय स्थान वाले को रू. 600/– तृतीय स्थान वाले को रू. 400/– का नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली टीम को रू. 4000/– द्वितीय को रू. 3000/– एवं तृतीय स्थान की टीम को रू. 2000/– नकद, प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाने वाली टीम को चल वैजयन्ती एवं राज्य स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के सभी छात्रों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

(4) राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल एवं टीचिंग एड् प्रतियोगिता

प्रतिवर्ष विभाग द्वारा राज्य के विद्यालयों के छात्रों में छिपी हुई सृजनात्मक प्रतिभा के विकास हेतु राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता तथा कम लागत के शैक्षिक उपकरणों के विकास हेतु अध्यापकों के लिए टीचिंग एड् प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राज्य में छिपी हुई प्रतिभाओं को न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा में प्रदर्शन का इस प्रतियोगिता के माध्यम से अवसर प्राप्त होते हैं। विगत 15 वर्षो से इस प्रतियोगिता के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने हेतु राज्य का प्रतिनिधित्व किया है।

अधिकतम छात्रों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथमतः खण्डस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता हैं। प्रत्येक खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रथम 3 व्यक्तिगत मॉडल, 3 टीम मॉडल एवं 3 शिक्षकों के टीचिंग एड् का चयन राज्य स्तरीय आयोजन में भाग लेने के लिए

किया जाता है। राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल एवं टीचिंग एड् प्रतियोगिता से विज्ञान मॉडल हेतु 3 टीम, 3 व्यक्ति, 3 शिक्षकों के टीचिंग एड् का चयन कर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले पश्चिम भारत विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए किया जाता हैं। राज्य स्तर पर चयनित प्रत्येक ग्रुप व्यक्तिगत, टीम एवं टीचिंग एड् में आये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान एवं सांत्वना (एक) प्राप्त करने वाले को क्रमशः रू..500/– रू.350/– रू.250/– एवं रू. 100/– तथा सभी संभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते है।

पश्चिम भारत विज्ञान मेला, 2011 मुम्बई के नेहरू साईन्स सेन्टर में आयोजित किया गया जिसमें 3 टीम व 3 व्यक्तिगत तथा 3 शिक्षक परियोजनाओं ने भाग लिया। राज्य के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिण्डवाडा, सिरोही के मॉडल कृषि क्षेत्र में नवीन तकनिकी के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।

(5) विद्यालय विज्ञान क्लब

राजकीय एवं निजी विद्यालयों में विज्ञान अध्यापकों की देख रेख में विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूचि विकसित करने तथा विज्ञान से संबंधित गतिविधियों, कार्यक्रमों को आयोजित कर सकने में योग्य बनाने के उद्देश्य से विद्यालय विज्ञान क्लबों की स्थापना की जाती है। बजट घोषणा अनुच्छेद 156 "राजीव गांधी विज्ञान क्लब योजना" अन्तर्गत 3171 विज्ञान क्लबों की स्थापना हेतु राशि रू. 3,17,10,000 की स्वीकृतियां जारी की गई। 1829 क्लबों की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी की जा रही है। विभाग द्वारा विज्ञान क्लबों को एक मुश्त राशि रू. 10000/– प्रति क्लब वित्तीय सहायता सहायतार्थ अनुदान के रूप में प्रदान करवायी जा रही है।

(6) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राज्य भर में समारोहपूर्वक आयोजित करने हेतु विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से साप्ताहिक कार्यक्रम 28.02.2012 से आयोजित किये जायेंगे। इन संस्थाओं द्वारा विज्ञान लोकप्रियकरण संबंधी विविध कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष दिनांक 28 फरवरी को आयोजित किये जाते है।

(7) बाल विज्ञान कांग्रेस

विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूचि विकसित करने खोज करने, पर्यावरण को समझने एवं वैज्ञानिक विधि से कार्य करने सम्बंधी जिज्ञासा उत्पन्न करने के उद्देश्य से बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2010–11 बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय "भूमि संसाधन – समृद्धि के उपयोग, भविष्य बचायें" रखा गया। बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन दो स्तरों पर किया जाता हैं। जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में शिक्षकों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात छात्रों द्वारा संदर्भ व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपनी–अपनी परियोजनाएँ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित की जाती है। प्राप्त परियोजनाओं को श्रोताओं के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जिला स्तर पर बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में चयनित परियोजनाओं को राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जाता है। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2010 को दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में

क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा चित्तौडगढ़ में किया गया। राज्य स्तर पर कुल प्रस्तुत 87 परियोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा 30 परियोजनाओं का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27–31 दिसम्बर, 2011 को जयपुर में विभाग द्वारा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में किया गया। इसमें 606 परियोजनाऐं प्रस्तुत की गयी, इन परियोजनाओं में से 25 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में 1 परियोजना राज्य की थी।

(8) विद्यालय विज्ञान केन्द्र

विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रूचि, स्वयं अपने हाथों से कार्य करने की प्रवृति बढ़ाने एवं उनमें विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई। इस वर्ष चयनित विद्यालय विज्ञान केन्द्रों को विभाग द्वारा रूपये 10,000/– प्रति केन्द्र अनुदान प्रदान किया गया। वर्ष 2011–12 में राज्य में कुल 8 विद्यालय विज्ञान केन्द्रों को सहायता प्रदान की गई है।

विज्ञान एवं समाज

राज्य के उपलब्ध संसाधनों के प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से विवेकपूर्ण दोहन एवं राज्य में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के उददेश्य से विभाग के विज्ञान एवं समाज प्रभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है।

इस प्रभाग के द्वारा सम्पादित की जा रही गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य देश की विभिन्न अनुसंधान संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की जा रही ग्रामोपयोगी तकनीकों/प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण की उपादेयता का आंकलन कर इन प्रौद्योगिकियों को राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना है। प्रभाग के अंतर्गत संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यकमों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण दस्तकारों, कर्मकारों एवं जन सामान्य तक नव विकसित प्रौद्योगिकियों की सम्यक जानकारी उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लक्षित समूह के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

विज्ञान एवं समाज प्रभाग के अंतर्गत निम्नांकित योजनाओं का क्रियान्वयन/संचालन किया जा रहा है:–

1 उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाईलेट/विशिष्ट परियोजनायें।
2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र।
3 विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी संदर्भ केन्द्र।
4 महिलाओं के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
5 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन।
6 टेक्नोलोजी प्रोक्योरमेंट एण्ड डवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर।
7 विज्ञान एवं समाज प्रभाग की गतिविधियों पर कार्यशाला।
8 ज्ञान नार्थ को कॉरपस फंड हेतु सहयोग।

1. उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाईलेट/विशिष्ट परियोजनायें

इस योजना के अंतर्गत राज्य की विशिष्ट समस्याओं जिनका समाधान प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से किया जा सके को चिन्हित कर उनके निराकरण हेतु पाईलेट प्रदर्शन परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के मूल्य संवर्धन द्वारा आय के अतिरिक्त अवसरों के सृजन हेतु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर आधारित विशिष्ट परियोजनाओं का निर्धारण भी किया गया है। विभाग द्वारा इन परियोजनाओं के लिये आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं सलाह का हस्तान्तरण विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं/प्रयोगशालाओं के समन्वय से किया जा रहा है।

आलौच्य वर्ष में प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न महत्तवपूर्ण कार्य किये गये।

- विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार, के वित्तीय सहयोग से खारे पानी के उपचार हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 5 प्रदर्शन परियोजनाओं का क्रियान्वयन भरतपुर, नागौर एवं झुंझुंनू जिले में किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम भोजडदेसर (सीकर) एवं ठीकरिया कलां (नागौर) एवं किसारी (झुंझुंनू) जिलों मे पूर्व में स्थापित रिवर्स ओस्मोसिस तकनीक पर आधारित संयत्रों का पर्यवेक्षण आलोच्य वर्ष में किया गया।
- राज्य आयोजना मद से आलोच्य वर्ष में खारे जल के शुद्धिकरण कर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयोजन से विभाग द्वारा केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर के तकनीकी समन्वय से राज्य के चिन्हित जिलों के 10 ग्रामों में थिन फिल्म कम्पोजिट आधारित रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रों की स्थापना की जायेंगी, जिनका संचालन एवं रखरखाव स्थानीय लाभार्थी समूह द्वारा किया जायेगा।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय सहयोग से बायोगैस एनरिचमेंट एवं पावर जनरेशन फॉर रुरल एप्लीकेशन परियोजना का राज्य की पांच चिन्हित गौ–शालाओं मे से कन्हैया गोशाला, जोधपुर, मुरली मनोहर गौशाला, बीकानेर में परियोजनान्तर्गत निर्धारित गतिविधियां पूर्ण कर ली गई है। शेष 3 गोशालाओं के कार्य प्रगति पर है।
- राज्य के महत्वपूर्ण मेलों में प्रौद्योगिकी शिविरों का आयोजन।
- आधारभूत नवाचार सशक्तिकरण नेटवर्क नार्थ के समन्वय से बायोमास ग्रैसीफायर एवं कम्पोस्ट एयरेटर पर प्रदर्शन कार्यकम का आयोजन।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से चूड़ी बनाने के लिये प्रयुक्त की जाने वाली भटटी परिवर्धन संबंधी परियोजना का कियान्वयन भरतपुर के दो चिन्हित स्थानों पर प्रगति पर है। अन्य परियोजना "शोसल डिफ्यूजन ऑफ इम्प्रुवड हैण्डपम्प" के अंतर्गत 500 हैण्ड पम्पों का परिवर्धन कार्य अजमेर भरतपुर, झुन्झूनू एवं उदयपुर जिलों में किया जायेगा एवं जल के समुचित उपयोग हेतु 500 पशु कुंडियों का निर्माण किया जायेगा।

2. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कियान्वित की जा रही इस योजना का लक्ष्य राज्य में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कार्यकमों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण गतिविधि के माध्यम से सुगम बनाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत नवीन प्रौद्यौगिकी आधारित चयनित विशिष्ट प्रशिक्षणों/जागरूकता के अतिरिक्त राज्य के लोकप्रिय ग्रामीण मेलों/प्रदर्शनियों में प्रौद्योगिकी

प्रदर्शन शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित उपयुक्त तकनीकों को प्रदर्शन के माध्यम से उनके हस्तान्तरण के साथ ही प्रयास किये जा रहे हैं।

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र ग्राम योजना का उद्देश्य एक चयनित ग्राम को केन्द्र बिन्दु बनाकर उस चयनित ग्राम एवं उसके परिधीय क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न अवयवों का चयनित क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुऐ व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन का मुख्य पहलु संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत किये जाने वाले दैनिक एवं संसाधनों पर आधारित गतिविधियों में अनुत्पादक तकनीकी को चिन्हित किया जाकर उस तकनीक का प्रतिस्थापन देश में विकसित उपयुक्त तकनीक द्वारा किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में निम्नांकित स्थानों पर स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं समन्वय से किया जा रहा है इस योजना के अर्न्तगत उर्जा आधारित ई–रिसोर्स की स्थापना की गयी जो ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना प्रौधोगिक आधारित सेवाऐ उपलब्ध करायेगा।

क्र.सं.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र का नाम	क्रियान्वयन एजेन्सी
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र, दादनपुरा, जिला जयपुर	कुमारप्पा ग्राम स्वराज संस्थान, बी–190, यूनिवर्सिटी मार्ग,जयपुर
2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र, जिला जोधपुर	थार वालेन्ट्री सोसाइटी, ई–22 पाल रोड, महावीर मार्ग,जोधपुर
3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र, चन्देसरा, जिला उदयपुर	विज्ञान समिति, रोड नं.17, अशोक नगर, उदयपुर
4	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र, बहादुरवास, जिला झुन्झूनू	समग्र विज्ञान संस्थान, झुन्झूनू
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र, ग्राम कंवरपुरा, जिला कोटा	राजस्थान पर्यावरण एवं विकास संस्थान, 4/373, भीम मंडी, कोटा
6	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र, ग्राम नग्गासर जिला बीकानेर	युवा भारत संस्थान, बीकानेर
7	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संदर्भ केन्द्र, नीमराना जिला अलवर।	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, पंजाब नेशनल बैंक, नीमराना जिला अलवर।
8	विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी संदर्भ केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर)	न्युपिन ह्युमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, भरतपुर
9	विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी संदर्भ केन्द्र कानपुरा श्रीनगर (अजमेर)	सवेरा संस्थान श्रीनगर अजमेर

4 महिलाओं के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार में महिलाओं की सहभागिता बढाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही इस योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही महिलाओं द्वारा संपादित की जाने वाली दैनिक गतिविधियों में नव विकसित तकनीक का समावेश कर कार्य करने की परिस्थितियों को कम श्रम साध्य एवं सरल बनाये जाने के

प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रौद्योगिकी अपनाने की क्षमता का निर्माण कर प्रौद्योगिकी पर आधारित गतिविधियों का निर्धारण किया गया। इन गतिविधियों में महिलाओं के विकास में संलग्न अन्य राजकीय विभागों, तकनीकी संस्थाओं तथा स्वयं सेवी संस्थानों के सहयोग एवं समन्वय से प्राप्त किया जा रहा है।

5 प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को आयोजन समारोहपूर्वक करने के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा इस दिवस पर विभिन्न सहयोगी संस्थानों के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी, संगोष्ठियां व शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों के व्याख्यान आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कृषि विकास केन्द्र, आबूसर, झुंझुंनू, में किया गया। समारोह में उन्नत प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई एवं आधारभूत नवप्रवर्तकों द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकियों का जीवन्त प्रदर्शन किया गया।

6. ज्ञान–नार्थ को कारपस फंड राशि का आवंटन

राज्य के आधारभूत स्तर के नवप्रवर्तकों को उदभवन, आदि प्रारूपण एवं विपणन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित आधारभूत नवाचार सशक्तिकरण नेटवर्क–नार्थ को आलोच्य वर्ष में धन राशि रू. 12.10 लाख कारपस फंड सहयोग राशि के रूप में आवंटित किये गये।

विज्ञान उद्यान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय करने के उद्देश्य से शास्त्री नगर, जयपुर में विज्ञान उद्यान विकसित किया गया है। यह उद्यान जन साधारण में, विशेष कर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्मित करने व विज्ञान के प्रति रूचि विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। यहॉ दैनिक किया–कलापों में निहित वैज्ञानिक सिद्धान्तों को मॉडल्स के माध्यम से खेल–खेल में समझाया गया है तथा वानस्पतिक महत्वता बताने हेतु औषधीय पौधों का खण्ड भी विकसित किया गया है। यहां करंज तेल से चलने वाले साधारण इंजन पम्प का प्रदर्शन भी किया जाता है।

आउटडोर मॉडल्स में डायनासोर, पी.एस.एल.वी. का मॉडल, एवं पवन चक्की प्रमुख है। विज्ञान उद्यान में प्राकृतिक हरियाली के बीच खुले में उर्जा, किया–प्रतिकिया, दृष्टि भ्रम, खनिज, गणित, यांत्रिकी, ध्वनि, पुल आदि के सिद्धान्तों पर आधारित मॉडल्स व फन साईन्स इनडोर गैलरी स्थापित है।

इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी दीर्घा का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के सहयोग से पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कम्प्यूटर अनुप्रयोग व संचार तकनीक प्रदर्शन के साथ–साथ "तारा–मण्डल" एवं टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष के रहस्यों को भी दर्शकों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

टेक्नोलोजी दिवस, विज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस आदि पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर इनकी महत्वता जन साधारण तक पहुंचायी जाती है।

यहां समय–समय पर ज्वलंत विषयों पर भी विद्यार्थियों हेतु लेक्चर आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विषय आधारित प्रर्दशनियों का भी आयोजन किया जाता है। इनमें विगत

वर्षों में 'इन टच विद टूमारो' सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रदर्शनी, 'बॉयोटेक्नोलोजी प्रदर्शनी जीवन का आर्विभाव' प्रदर्शनी, भौतिक शास्त्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों की प्रदर्शनी तथा हयुमन जीनोम पर आधारित चल प्रदर्शनी काफी लोकप्रिय रही। वित्तीय वर्ष 2010–11 में विद्यालयों द्वारा अपने वार्षिक समारोह विज्ञान उद्यान में आयोजित किये एवं इन विद्यालयों को विज्ञान उद्यान की गतिविधियों/कार्यक्रमों से जोड़ा गया।

विज्ञान पर आधारित कार्यशालाओं का भी आयोजन विगत वर्षों में किया गया है जैसे सरकारी विद्यालयों की छात्राओं हेतु कम्प्यूटर पर कार्यशालायें, इलैक्ट्रोनिक कार्यशाला, मॉडल निर्माण कार्यशाला, वैज्ञानिक नुक्कड़ नाटक, पर्यावरण, जल व वायु की जांच पर कार्यशाला। यातायात के नियमों का विज्ञान जन सामान्य तक सरलता से पहुंचाने हेतु विज्ञान उद्यान में ट्रैफिक पार्क का निर्माण भी किया गया है, जहां यातायात पुलिस के माध्यम से जन–साधारण को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक तथा अपडेट किया जाता है। यहां प्रतिवर्ष जनवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है।

उद्यान में रोटेटिंग ग्रेनाइट पिलर भी स्थापित है जो कि हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग आधार पर चलता है। एक बैटरी चलित वाहन से दर्शकों को विज्ञान उद्यान परिसर भ्रमण कराया जाता है। यह वाहन मितव्ययी, शोररहित, पर्यावरण मित्र तथा विद्युत संचालित है। झालरापाटन (झालावाड़) में 5 एकड़ भूमि में साईंस पार्क संचालित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र :– विज्ञान उद्यान परिसर में ही क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र भारत सरकार के 50 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से विकसित किया जा रहा है। कुल रू. 8.50 करोड की लागत से बन रहे, इस विज्ञान केन्द्र में 3–डी थियेटर, 150 सीट का ऑडिटोरियम, तरामण्डल के साथ साथ बायो मेडिकल इवोल्युशन, एस्ट्रोनॉमी व फन साईन्स पर वृहद दीर्घायें होंगी।

उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र जोधपुर– भारत सरकार के 50 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से रू. 2.60 करोड़ की कुल पूंजीगत लागत से जोधपुर में भी उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का कार्य प्रगति पर है।

सांईस पार्क उदयपुर– जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के वित्तीय सहयोग से उदयपुर में भी सांईस पार्क के निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है।

उद्यमिता विकास

1. उद्यमिता जागृति शिविर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ग के विद्यार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्य के शिक्षण संस्थाओं तथा इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्नीक/आई.टी.आई./ विज्ञान संकाय कॉलेज इत्यादि में तीन दिवसीय उद्यमिता जागृति शिविरों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। आलोच्य वर्ष में 65 उद्यमिता जागृति शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 37 शिवरों का आयोजन किया जा चुका है।

2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ग के स्नातक विद्यार्थियों को स्वयं के उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, लघु उद्योग विकास बैंक, नाबार्ड, रूडसैट, उद्यमिता प्रबंधन संस्था इत्यादि के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से 4–6 सप्ताह

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन विभाग द्वारा करवाया जाता है। कार्यक्रम में रोजगार स्थापित करने संबंधित समस्त जानकारियों से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 2 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राशि रू. 1,00,000/– की स्वीकृति जारी की गई। 3 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन की स्वीकृति जारी की जा रही है।

कौशल विकास कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल विकास हेतु 4–6 सप्ताह के कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन विभाग द्वारा करवाया जाता है। इस कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ग के आई.टी.आई./विज्ञान वर्ग पास विद्यार्थियों को स्वरोजगार अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण करवाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 5 कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास प्रभाग के अंतर्गत विभाग द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो राज्य के साधारण नागरिक के जीवन स्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक सुधार करने में सहायक सिद्ध हो।

1. अनुसंधान एवं विकास परियोजनायें

योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिकी, महाविद्यालयों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं एवं राजकीय व अर्द्ध–शासकीय विभागों/संस्थाओं से अनुसंधान एवं विकास परियोजनायें आमंत्रित की जाती है। राज्य की ज्वलंत व मूलभूत समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विषय विशेषज्ञों की अनुशंषा के आधार पर चयनित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आलोच्य वित्तीय वर्ष में उदयपुर संभाग से प्राप्त 25 वृहद अनुसंधान परियोजनाओं में से 20 अनुसंधान परियोजनाओं का मुल्यांकन विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा किया जा चुका है तथा जयपुर, कोटा एवं बीकानेर संभाग की प्राप्त परियोजना प्रस्ताव समिति के समक्ष विचाराधीन है।

2. विद्यार्थी परियोजना कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान विद्यार्थियों से उनके अध्ययन काल में ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से जन साधारण को लाभन्वित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किये जाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान एवं अन्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विज्ञान संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थी अपने प्राध्यापक के दिशा निर्देशन में एक वर्ष के लिये स्वीकृत विद्यार्थी परियोजना पूर्ण करतें हैं। वर्ष 2011–12 में इन परियोजनाओं का चयन, संबंधित विभिन्न विषय विशेषज्ञों की अनुशंसा के आधार पर किया गया है और उन्हें मूर्त रूप देने के लिये अधिकतम रू.15000/– प्रति परियोजना की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 870 प्रस्ताव प्राप्त कर लिये गये हैं। जिनका मुल्यांकन चिन्हित विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। आलोच्य वित्तीय वर्ष में अनुमानित 300 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 30.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा रही है।

3. कार्यशाला/सेमीनार/कॉन्फ्रेन्स/मीटिंग्स

विज्ञान के दिन–प्रतिदिन बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में हुई नवीनतम खोज/ उपलब्धियों के विचार–विमर्श एवं प्रचार प्रसार हेतु समय–समय पर आयोजित होने वाली कार्यशालायें/सेमीनार व बैठकों के लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उत्प्रेरक राशि के रूप में प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में अब तक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के विभिन्न 30 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमे से 13 प्रस्तावों को रू0 3.25 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी गयी। नैनो टैक्नोलॉजी संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है।

4. परम्परागत अनुसंधान एवं विकास परियोजनायें

परम्परागत वैज्ञानिक तकनीक जो लुप्त हो रही हैं उनको संरक्षित एवं पुनर्जीवित तथा उनको विकसित करने के लिये भी विभाग निरंतर प्रयासरत है। उनके आधुनिक तकनीकों के सम्मिश्रण/परिष्कृत करने हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजना विभाग द्वारा विशेषज्ञ सलाहकार समिति की अनुशंसा के आधार पर हाथ में ली जावेगी।

5. एप्लाईड रिसर्च सेंटर

एप्लाईड रिसर्च सेंटर का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं द्वारा कियान्वित सफल परियोजनाओं के परिणामों को लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इन संस्थानों की पहचान कर उनसे ज्वलन्त समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर परियोजनायें तैयार करवाने के पश्चात वर्ष 2011–12 में वित्तीय सहायता प्रदान कर कियान्वित किया गया।

एम एल सुखाडिया युनिवर्सीटी उदयपुर में माईनिंग हैजार्ड्स पर एप्लाईड रिसर्च सेन्टर, स्थापित है। केन्द्र द्वारा खनिज उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसका अन्तिम प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित किया जा रहा है। इस वर्ष विभाग को राजस्थान विश्व विद्यालय एवं कोटा विश्वविद्यालय से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुये है।

6. ट्रेवल सपोर्ट

इस योजना के अर्न्तगत राज्य के वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/ कॉंफ्रेन्स में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत 03 वैज्ञानिक को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

जैव प्रौद्योगिकी

पिछले चार दशक आधुनिक जीव विज्ञान के युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कम्प्यूटर आधारित सूचना, संचार तथा प्रभावशाली यंत्रीकरण के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति के साथ–साथ जीव विज्ञान, खाद्य, चारा पशु उत्पादकता, जन स्वास्थ्य, पर्यावरण व उर्जा के क्षेत्रों में नये तथा अब तक अकल्पित उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के अग्रदूत के रूप में सामने आया है। जैव प्रौद्योगिकी वास्तव में सूक्ष्म जीवों, जन्तु एवं पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिये उपयोगी उत्पादों का उत्पादन है। अतः भविष्य में जैविक साधनों का उपयोग, बढी हुई कृषि उत्पादकता, पोषण सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्वच्छ वातावरण और रोजगार अवसरों के सृजन में सहायक होगा।

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स

इस योजनान्तर्गत महात्मागांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाईड साइन्स, जयपुर में सेन्टर विद पोटेन्शिल फॉर एक्सीलेन्स की स्थापना वर्ष 2008–09 में की गयी है। वर्ष 2011–12 के दौरान राशि रू 1.55 लाख की सहायता उपलब्ध करवायी गयी। केन्द्र द्वारा परियोजना पूर्ण की जाकर अन्तिम रिपोर्ट विभाग को प्रेषित कर दी गई है।

पेटेन्ट सूचना केन्द्र

वर्ष 1998 में प्रौद्योगिकी सूचना एवं पूर्वानुमान परिषद, (टाईफेक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता द्वारा विज्ञान उद्यान, शास्त्री नगर, जयपुर में पेटेन्ट सूचना केन्द्र स्थापित किया गया। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रति जागरूकता हेतु यह केन्द्र अब तक राजस्थान के विभिन्न शहरों में 30 कार्यशालाऐं एवं 80 बौद्धिक सम्पदा अधिकार कैम्पों का आयोजन कर चुका है। इस केन्द्र द्वारा अब तक 19 पेटेन्ट, 3 डिजाईन एवं 4 कापी राईट के आवेदन पेटेन्ट सुविधा केन्द्र, भारत सरकार, नई दिल्ली को अग्रेषित किये गये हैं। जिसमे एक पेटेन्ट तीन डिजाईन 1 कापी राईट के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये है।

पेटेन्ट सूचना केन्द्र राजस्थान द्वारा अब तक 19 पेटेन्ट सर्च रिपोर्ट तैयार की गई है। अब तक कार्यशालाओं व बौद्धिक सम्पदा अधिकार कैम्पों द्वारा लगभग 12000 सम्भागियों को लाभान्वित किया गया।

पेटेन्ट सूचना केन्द्र के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध राशि से 5 आई.पी.आर. विश्वविद्यालय सैल जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर एवं कोटा में स्थापित किये गये हैं।

वर्ष 2010 में भौगोलिक सम्पदा अधिकार पर विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के लिये राज्य सरकर द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें राज्य के किसी भौगोलिक सूचक को विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार में पंजीकरण हेतु भिजवाया जा सकेगा। पेटेन्ट सूचना केन्द्र के माध्यम से बीकानेरी भुजिया का भौगोलिक सम्पदा अधिकर में पंजीकरण कराया जा चुका है।

वर्ष 2010 में सुक्ष्म, मध्यम औद्योगिकी क्षेत्रों के लिये केन्द्र सरकार की सहायता से बौद्धिक सम्पदा अधिकार जागरूकता हेतु एक आई.पी.एफ.सी. केन्द्र, विज्ञान उद्यान मे स्थापित किया गया है। यह परियोजना तीन वर्ष हेतु है जो कि पेटेन्ट सूचना केन्द्र के साथ कार्य करेगी। औद्योगिक क्षेत्रों हेतु जयपुर एवं जोधपुर में दो एक दिवसीय कार्यशालाओं को आयोजन बौद्धिक सम्पदा अधिकार जागरूकता हेतु किया गया।